



श्रतापारता

EXTRAORDINARY

भाग I---खण्ड I

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 110]

नई विल्ली, शशियार, जूलाई 19, 1969/झाषाब् 28, 1891

No. IIO

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, '1969/ASADHA 28, 1891

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (Department of Labour and Employment)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th July 1969

No. 31/7/68-LRIV.—The socio-ectnomic effects of the introduction of automation measures in industry, commerce, administration and other related fields have recently been the subject of a good deal of debate in the country. It has been urged that automation reduces employment potential in individual industries and occupations; on the other hand, it has been argued that automation is part of the modern technological progress, is indispensable for industrial and economic development and helps to create new industries and expand existing industries in manner which would not be possible without automation. Certain export-oriented industries have also pleaded that, without automation, they cannot compete in foreign markets with manufacturers from other countries which place no restrictions on automation. Government's policy in this regard has been that automation could be introduced but on a selective basis and that technological advance should be regulated to make it consistent with the social good of the community. The criteria which determine such selectivity need to be more elearly defined and for this purpose the Government have decided to set up a Committee.

2. The Committee will consist of the following:

Chairman

Shri R. Venkataraman—Member, Planning Commission.

Mem⁺ers

- 1. Shri G. Ramanulam.
- 2. Shri Bagaram Tulpule.
- Shri Satish Loomba.
- 4. Shri B. D. Somani.
- 5. Shri Babubhai M. Chinai.
- 6. Shri Naval H. Tata
- Prof. V. M. Dandekar, Director, Gokhale Institute of Economics & Politics, Poona.
- 8. Prof. V. R. Rao, Computer Centre, Delhi.
- 9. Brig. B. J. Shahaney, National Instruments, Kotah.
- 10. Dr. B. S. Garud, General, Manager, Shrivam Fertilisers.
- 3. The following will be the terms of reference of the Committee:-
 - (1) To review the total effects of the operation of automation in the enterprises in the public and private sectors in which it has been already introduced.
 - (2) To recommend criteria for the determination of any specific areas and fields in which introduction of measures of automation, including computers, may be permitted or restricted with due regard to—
 - (i) the need for raising efficiency and productivity in industry and trade, and in particular industries which are export-oriented;
 - (ii) the requirements of scientific research and development;
 - (iii) the need for the timely tabulation, analysis, study, etc. of the large masses of data that arise in modern industry, trade, transport, etc; and
 - (iv) the need for restricting the import of foreign equipment for automation and for encouraging the use of such equipment manufactured in the country.
 - (3) To recommend safe-guards for avoiding or minimizing any harmful social effects of the introduction of automation;
 - (4) To consider and make recommendations on any other related matters.
- 4. The Committee is requested to submit its report within a period of one year.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Part I Section (I).

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministres/Departments of the Government of India, State Governments/Administration of Union Territories and all other concerned.

No. 31/7/68-LRIV P. M. NAYAK, Secv.

अन, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम ग्रौर रेजगार त्रिभाग)

मंक्टब

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1969

संख्या 31/7/68-एल० आर० 4: ---उद्योग, वाणिज्य, प्रशासन श्रीर अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में स्वचालित मशीनों के लगाने से होत वाले नामाजिक-ग्राधिक परिणाम इस देश में हाल ही में काफी चर्चा के विषय रहें हैं। एक श्रोर यह कहा जाता है कि जिस उद्योग श्रीर कारोबार में स्वचालित मशीनें लगाई जाती हैं, वहां रोजगार ले श्रवणर वम हो जाते हैं, दूसरी श्रोर यह दलील

दो जाती है कि प्यवालक आश्रतिक प्रौद्योगिकी की प्रगति का एक ग्रंग है, वह प्रौद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए अरिहा है श्रौर बढ़ नये उद्योगों के निर्माण तथा अर्तमान उद्योगों के विस्तार में इन तरीके से महायता देता है जो इसके बिना संभव नहीं निर्मात करने वाले कुछ उद्योगों ने भी यह दलील दी है कि बिना स्वचालन के ये ऐसे अन्य देशों के निर्माताओं से विदेशी बाजारों में नुकाबला नहीं कर सकते, जिन्होंने स्तचालन के प्रयोग पर कोई रोक नहीं जगाई है। इस सम्बन्ध में नरकार की नीति यह रही है कि स्ववालित मर्शानें लगाई जा सकती हैं, लेकिन चयनात्मक आश्रार पर और यह कि प्रौद्योगिक प्रगति का जिनियमन ऐसा किया जाना चाहिए कि वह जन हित के अनुस्थ हो। इस प्रकार की चयनात्मकता की कसौदी का निर्धारण और स्पष्ट रूप से किये जाने की आवश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए सरकार ने एक समिति की स्थापना करने का निर्णय किया है।

2. इस निमिति में निम्निविधित व्यक्ति होंगे :--

ऋः स

1. श्री ग्रार० वेंकटारमन, सदस्य, योजना ग्रायोग ।

सवस्य

- 1. श्री जी० रामानुजम ।
- 2. श्री बागाराम तुलपुले।
- 3. श्री सतीश लूम्बा।
- 4. श्री बी० डी० सोमानी।
- 5. श्री बाब्भाई एम० चिनाई।
- 6. श्री नवल एच० टाटा।
- 7. प्रो० बी० एन० दांग्डेकर,

निदेशक,

गोखले शंस्टिट्यूट भ्राफ इक्नोमिक्स एण्ड पोलिटिक्स, पूना ।

- प्रो० बी० म्रार० राव,
 कम्प्युटर सेंटर, दिल्ली ।
- क्रिगेडियर बी० जे० साहनी, नैशनल इन्स्ट्रमेंट्स, कोटा।
- 10 डा० बी० एस० गरुड़ , जनरल मैनेजर, श्रीराम फर्टिलाइजर्स ।
- 3. इस समिति के विचाराणीय-विषय निम्नलिखित होंगे :---
 - (1) जिन सरकारी और गैर-सरकारी उद्यमों में स्वचालित मशीनें लगाई जा चूकी हैं उनमें उनके चलाये जाने से हुए कुल परिणामों का पुनरीक्षण करना;
 - (2) ऐसे किन्हीं विशेष क्षेत्रों को निश्चित करने की कसौटियों की सिफारिण करना जिन में संगणक समेत स्वचालित मशीनें लगाने की श्रनुमित दी जा सके प्रथवा निम्न बातों को ध्यान में रख कर रोक लगाई जा सके:—
 - () उद्योग ग्रौर कारोबार में ग्रौर विशेष कर निर्यात करने वाले उद्योगों में कार्य-प्रवीणता एवम उत्पादकता बढ़ाने की ग्रावश्यकता ;

- (ii) वैज्ञानिक श्रनुसंधान तथा विकास की प्रिप्रावश्यकताये ;
- (iii) आधुनिक उद्योग, कारोबार, पित्वहन इत्यादि के बड़ी माला में आंकडों की उचित समय पर तालिकायें बनाने विश्लवण, अध्ययन आदि करने की श्रावश्यकता;
 और
- (iv) स्वचालन के लिए विदेशों मे निर्मित सामान के श्रायात पर रोक लगाने श्रीर देश के डो श्रन्दर बने ऐसे सामान के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की श्राव-स्यकता ।
- (3) स्वचालित मशोनों के लगाने ने उत्पन्न होने वाले हानिकर सामाजिक प्रभावों को कम-से-कम करने प्रथवा उन्हों न होने देने के लिए सुरक्षात्मक उपायों की सिफारिश करना ;
- (1) किसी अन्य राजद विषयों के वारे मे विचार करना और सिफारिशें करना।
- 4. इस समिति से एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आर्थना की जाती है।

ग्रादेश

भादेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपन के भाग 1, राणड (1) में प्रकाणित किया जाय।

यह भी ब्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संबीय क्षोत्रों के प्रशासनों तथा ध्रन्य सभी संबंधिनों को भेज दी जाय।

पी० एम० नायक, सचिव ।